

संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार का औचित्य क्या है!

- लोकतंत्र के मंदिर की पवित्रता पर इस फैसले से लगेगा दाग
- इंदिरा गांधी ने किया था पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन
- इस तरह के आयोजनों को सियासत से दूर रखा जाना चाहिए

लोकतांत्रिक व्यवस्था की परिकल्पना में सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिकाओं को परिभ्रमित तो किया गया है, लेकिन दोनों पक्षों की भूमिका वह है कि वे अपने विशेष रूप से लागू होती हैं, जहां विपक्ष का मतलब सत्ता पक्ष के द्वारा कदम का विरोध माना जाता है। अब नये संसद भवन के उद्घाटन को लेकर मचे सियासी संघरण को ही लिया जाये। प्रायानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को इस नये संसद भवन का उद्घाटन करनेवाले हैं, लेकिन विपक्षी दलों ने देश की गिरावट के इस समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा की है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि सर्वोच्च संवैधानिक पद पर होने का नाम

राष्ट्रपति को नये संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि समारोह में राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाना दोनों का अपमान है।

संपादकीय

लोगों की उलझन दूर करें

दो हजार रुपये के नोटों की वापसी की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गयी। अग्र बैंकों से लंबी कतारें लगने वा बेहिसब भीड़ जमा हो जाने की खबरें नहीं आ रहीं तो इसकी एक बजह तो यही है कि इन नोटों का चलन काफी फहले से कम होता जा रहा था। अग्रबीआइ के अंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च 2023 को सुकर्लेशन में मौजूद दो हजार के नोटों की संख्या कुल नोटों का 10.8 फीसदी ही रह गयी थी। दूसरी बजह वह भी हो सकती है कि पिछली बार वारी 2016 में हुई नोटबंदी के विपरीत इस बार इन नोटों का लोगल टेंडर बनाये रखा गया है। इन्हें बदले जाने की सम्भासी भी लंबी (30 सितंबर तक) रखी गयी है। सोमवार को खुद अग्रबीआइ गवर्नर ने स्पष्ट किया कि 30 सितंबर के बाद भी ये गत मान्य होंगे और वह संकेत भी दिया जिसके जरूरत होने पर यह सम्भासी बढ़ायी जा सकती है। बाबूआबू इसके दो हजार के नोट वापस लिये जाने की घोषणा करनी भैन्जमेंट के लिहाज से कोई अच्छी मिमाल नहीं कही जायेगी। घल ही आबाबी का बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर इस फैसले से प्रभावित न हो रहा है, लेकिन इसमें हर आम ओ खास के लिए सरप्राइज एंटीमेंट जरूर है। इसन सबको न केवल एक बार चौंका दिया, बल्कि उनके जेहान में दोनों नोटबंदी के कड़वे अनुचर को फिर ताजा कर दिया। इसके अलावा नोटबंदी के पुकाबले ज्यादा सकर्ता और ज्यादा सहजता से अमल किये जाने के प्रयासों के बावजूद इस बार भी अनिश्चितता और असर्मजस की स्थिति दाली नहीं जा सकी। सोमवार को आये आग्रबीआइ गवर्नर के स्पष्टीकरण के बाद भी अभी तक जरूरत होनी है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अलग-अलग बैंकों की ओर से बताया जा रहा है कि इसकी जरूरत होगी। यह भी तय नहीं है कि एक बार में अधिकतम 10 नोट बदलवाने की रीमां का बाबा मतलब है। बाबा यह सीमा एक दिन के लिए है या कतारें कोंडांटर पर आगे वाली अपनी बारी से मतलब है। यारी का उत्ती समय दोबारा कतार में लगकर कोई चारों तो दूसरी बार भी 10-10 नोट बदलवा सकता है? इसके अलावा नोट वापसी की इस घोषणा ने यह विचारित स्थिति पैदा कर दी है कि दो हजार के जो नोट देश में चुनाव होने पर भाजपा ने 2014 में नोटबंदी की जारी रखी थी और इस कैफियत से नुकसान की भरपाई की है।

नोट वापसी की इस घोषणा ने
यह विचारित स्थिति पैदा कर दी है कि दो हजार के जो नोट देश की कर्पंसी का हिस्सा है और आज नीं लीगल टेंडर है, बाजार में स्वीकार नहीं किये जा रहे।

स्पष्टीकरण के बाद भी अभी तक यह साफ नहीं है कि नोट बदलने के लिए बैंक जाने वालों को आइडी दियाने और फॉर्म भरने की जरूरत होगी या नहीं। एसबीआइ की घोषणा के मुताबिक इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अलग-अलग बैंकों की ओर से बताया जा रहा है कि इसकी जरूरत होगी। यह भी तय नहीं है कि एक बार में अधिकतम 10 नोट बदलवाने की रीमां का बाबा मतलब है। बाबा यह सीमा एक दिन के लिए है या कतारें कोंडांटर पर आगे वाली अपनी बारी से मतलब है। यारी का उत्ती समय दोबारा कतार में लगकर कोई चारों तो दूसरी बार भी 10-10 नोट बदलवा सकता है? इसके अलावा नोट वापसी की इस घोषणा ने यह विचारित स्थिति पैदा कर दी है कि दो हजार के जो नोट देश की कर्पंसी का हिस्सा हैं और आज भी लीगल टेंडर है, बाजार में स्वीकार करनी जरूर है। इस स्थिति को निःशेष हाला जासकता था। हालांकि यह बात रेखांकित किये जाने की जरूरत है कि अपने देश में कर्पंसी की साख काफी अच्छी है। वरना डिजिटल ट्रांजेक्शन की इन्वेन्टरी तेज और सहज प्रक्रिया संभव नहीं थी, लेकिन हमारे नीति-निर्माणीयों को पॉलिसी की स्पृहता से जुड़े सबकों पर यह साधारण फिर से गैर करने की जरूरत है।

अभिमत आजाद सिपाही

कर्नाटक की जीत ने निर्विवाद रूप से शासन परिवर्तन घाने वालों को उत्साह की एक बूस्टर खुलाक दी है। पिछले 4 महीनों में भाजपा ने 2 राज्य सरकारों पर नियंत्रण खो दिया है, जबकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी (आप) से पंजाब में हुए नुकसान की भरपाई की है। नीतीजतन, इस साल के अंत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पुनाव होने पर भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल दोनों के लिए दासगुप्ता

स्वप्न दासगुप्ता

कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जोरदार जीत का एक अनपेक्षित परिणाम भारत की रेटिंग को चुनावी निरंकुशता से चुनावी लोकतंत्र में अचानक अप्रृथक करता है। कम से कम उन लोगों की नजर में, जो खुशआरी डालनग्रीडिंग के लिए जिम्मेदार थे। 2014 के बाद से अनाथ और 2019 के बाद से स्पष्ट रूप से कड़वे एक बौद्धिक परिस्थितिकी तंत्र की प्रतिक्रिया इतनी उत्साहजनक रही कि विस्तृत ब्लॉप्रिंट पहले से ही एक बिंदु के उद्देश्य के लिए तैयार किये जा रहे हैं- 2024 में नरेंद्र मोदी के हार। कर्नाटक की जीत ने नियंत्रित रूप से शासन परिवर्तन घाने वालों को उत्साह की एक बूस्टर खुलाक दी है। पिछले 4 महीनों में भाजपा ने 2 राज्य सरकारों पर नियंत्रण खो दिया है, जबकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी (आप) से पंजाब में हुए नुकसान की भरपाई की है।

नीतीजतन, इस साल में चुनाव होने पर भाजपा

और अधिकारी दल दोनों के लिए दाव उंचे हैं। यदि

अधियान के अंतिम सप्ताह में कर्नाटक में राजनीति देष्पूर्ण लग रही थी तो आप चुनाव से पहले के मरीजों में यह दोगुनी हो सकती है। अपने दक्षिणी गढ़ पर पकड़ बनाने में भाजपा की

विफलता की निश्चित रूप से

पार्टी द्वारा आंतरिक तौर पर चौर-

फाइ की जायेगी, जबकि इसके

विवरणीय फैसले की व्याख्या कठोर हिंदू राष्ट्रवाद की एक जोरदार

अस्वीकृति के रूप में कर सकते हैं



कांग्रेस के विचारों को जातिगत जोड़-तोड़, काल्पनिक राजनीतिक एकता और भारत के विचार के उपरों से कहीं अधिक, इस प्रणालित सामाज्य ज्ञान को तोड़ने की आवश्यकता होगी कि भारत सुरक्षित है और मोदी के नेतृत्व में बेहतर स्थिति में है। अस्तित्वगत द्विविधाओं से अंगूष्ठ कांग्रेस के लिए कर्नाटक की जीत आंतरिक शक्ति समीकरणों को नई आकृति प्रदान कर सकती है।

और अविश्वसनीय धर्मनिरपेक्षता के अधियान पर इसकी संभावनाओं को जोड़ सकते हैं। भाजपा द्वारा एक बहुत अलग निष्कर्ष निकालने की संभावना है।

अधियान के अंतिम चरण में भगवा रंग को बुलंद करने का एक स्पष्ट उद्देश्य था- पार्टी के पासपरिक मरीजों में किए गए प्रेरित करना, जो अन्यथा अपनी सरकार के कमज़ोर प्रदर्शन से निराश है। अपने 36 प्रतिवान वोट शेयर को बनाये रखने में भाजपा की सफलता कोई छोटी उपलब्धिता नहीं थी और यह पूरी तरह से एक उच्च भावनात्मक मोर्चे पर अधियान के समापन के कारण था। प्रचार के अखिरी दिनों में पूरी तरह से

‘वैचारिक’ गला घोटना भाजपा के अधियानों की विशेषता रही है।

हालांकि उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में यह साश्ल इंजीनियरिंग से पहले था और शासन के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करता था। यह दृष्टिकोण तकानटक में इनकी कमी थी। यही कारण है कि अंतिम ओरेवरों में हिंदू ढोल-नगाड़ों ने कांग्रेस के चारों ओर विशेष रूप से क्षेत्रीय दलों का सामना करते समय भाजपा की अपराध के लिए दोषीय आकृति को एकजुट किया, मार रहे हैं और विशेष रूप से भुनाने में असमर्थ रहती है। राज्य के नेताओं को सशक्त बनाना और स्थानीय और राष्ट्रीय के बीच एक प्राधानमंत्री की अपनी ‘पंथ अपील’ के अलावा, कर्नाटक अधियान के दौरान भी भाजपा सरकार के पास विकास कार्यालय और राष्ट्रीय के बीच एक पारस्परिक रूप से लाभप्रद तालमेल विकसित करना ऐसी चुनौतियां हैं, जिन्हें पार्टी को इस स्थानीय अधिकारी योजनाओं की विविधता के लिए लाभ दिया जाता है।

कर्नाटक की दिवालिया कर देंगी। ऐसे लागता है कि हिंदू एकजुटा केवल आक्रमक हिंदुत्व पर नहीं होती, इसे शासन और कल्याण पर नहीं होती।

एसेक्यूरिटी के लिए दाव उंचे हैं। यदि

<p

देश-विदेश / ओडिशा

सीएम की समीक्षा के बाद विभागीय सचिव ने दी जानकारी

राज्य के गरीबों के बीच बहुत जल्द बाटे जायेंगे नौ लाख घर

- मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है
- अगले एक साल के मीटर सभी लॉकों में निशन थकि कैफे का निर्णय और संचालन किया जायेगा

आजाद सिपाही संवाददाता

भूवनेश्वर। बहुत जल्द गरीब लोगों के सिप छत बनेंगी। यह घोषणा की गई है कि राज्य के निवासियों को 9 लाख आवासीय घर प्रिवारित किया जायेगा। ओडिशा में जो 9 लाख आवासीय घर आए हैं, उन्हें सरकार द्वारा जल्द ही वास्तविक लाभाधिकारों को वितरित किया जायेगा। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है। पचास तीराज एवं पेयजल मंत्री प्रदीप कुमार



अमत ने इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक ने विभाग के कामकाज की समीक्षा के बाद यह आदेश दिया। राज्य के सभी प्रबंधियों एवं रिक्टर पड़े सरकारी भवनों को 3 माह के अन्दर स्थानीय मिशन शक्ति समूहों को हस्तान्तरित करना। ओआरएमएस के साथ मिशन शक्ति मोड में स्थानीय किया जायेगा। अगले एक साल के बाद यह फैसला लिया गया है।

भीतर सभी लॉकों में मिशन शक्ति कैफे का निर्णय और संचालन किया जायेगा। विभिन्न स्थानों पर अनुवयोंगी एवं रिक्टर पड़े सरकारी भवनों को 3 माह के अन्दर स्थानीय मिशन शक्ति समूहों को अधिक कुशल बनाएं। सभी घरों में पेयजल आपूर्ति को

प्राथमिकता दें। अब तक, राज्य के 61% ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध करवा रहा गया है। 57,000 करोड़ रुपये की लागत से 206 मेगा पेयजल परियोजनाएं और 13 हजार सिंगिल पिलेज पाइप जलापर्ति परियोजनाएं शुरू की गयी हैं।

हर पंचायत में चलेगी 'मो बस'
परिवहन सचिव ने दी जानकारी

भूवनेश्वर (आजाद सिपाही)। हर पंचायत में मो बस चलने का निर्णय लिया गया है। अब मो बस प्रखण्ड मुख्यालय से हर पंचायत तक चलेंगी। परिवहन सचिव उप पाठी ने इसकी जानकारी दी। राज्य सरकार ने ऐसा कर्तम उठाने का देखते हुए राज्य सरकार ने ऐसा कर्तम उठाया है। जानकारी के अनुसार लझी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा उपलब्ध करायेगी। पहले चरण में 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जायेगा। बाद में इसे अब जिलों में चलाया जायेगा। मो बस को कोरोटु, नवगंगु, रायगढ़, मालकानगरी, कलाहांडी और गजपति जिलों में चलाने का निर्णय लिया गया है। उक्त 6 जिलों में लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में उनकी परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने ऐसा कर्तम उठाया है। परिवहन सचिव उप पाठी ने हर पंचायत में मो बसों के संचालन की जानकारी दी।